

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2

संख्या: /VII-A-2/2021/17-उद्योग/2013
देहरादून : दिनांक ३१ दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

चूंकि, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-556/VII-2/2015/17-उद्योग/2013 दिनांक 28.07.2015 द्वारा लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्राख्यापित मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति-2015, जिसमें शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1033/VII-1/17-उद्योग/2013 TC, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016, कार्यालय ज्ञाप संख्या-358(1)/VII-1/2018/17-उद्योग/2013 TC, दिनांक 25 मई, 2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-236/VII-A-2/2020/17-उद्योग/2013 दिनांक 11 जून, 2020 से समय-समय पर संशोधन भी किये गये हैं;

और चूंकि, नीतिगत कार्यों में सुगमता तथा सरलीकरण के दृष्टिगत उक्त नीति में किये गये संशोधनों को समाहित करते हुये नयी एकीकृत नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है;

अतः अब राज्यपाल, उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास दर में वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु निम्नवत् नयी 'मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति, 2021' प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. इस नीति का संक्षिप्त नाम 'मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021' है।
- ii. इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार (उद्योग विभाग/सिडकुल) द्वारा विकसित सभी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, अधिसूचित निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/ विशेष औद्योगिक क्षेत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2003-सीई दिनांक 10 जून, 2003 में Proposed Industrial Estates/Area व Expansion of the Existing Industrial Estates शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों अथवा मेगा गोजेक्ट्स के लिए विधिक रूप से अर्जित ऐसी भूमि, जिसका भू-उपयोग विनियमित क्षेत्र के अनुमोदित मास्टर प्लान में औद्योगिक या व्यवसायिक अथवा सेवा क्षेत्र की अनुमन्य गतिविधि के संचालन के लिए सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत किया गया हो, अथवा विनियमित क्षेत्र से बाहर (नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) की भूमि, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 143 सप्टित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 135 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक/अकृषक घोषित की गयी हो, आच्छादित होंगे।

स्पष्टीकरण: उक्त प्रावधान मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2015 (यथासंशोधित)-2016, 2018 व 2020 के अन्तर्गत स्थापित हो रही ऐसी परियोजनाओं पर भी लागू होंगी, जेन्होंने इस नीति के प्रवृत्त होने से पूर्व अपनी परियोजना की स्थापना के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर सभी सम्बन्धित विभागों से वांछित स्वीकृतियां/निराक्षेप/अनुज्ञा प्राप्त कर उद्यम स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी हो।

iii. इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विकसित/अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा अन्य अभिज्ञात स्थलों पर स्थापित होने वाली निम्नलिखित चिन्हित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र की नयी परियोजनायें और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाईयां नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी:-

(अ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग): भारत सरकार की अधिसूचना फा.सं. 2(2)/2018-एसपीएस-दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के अनुबन्ध-1 में निषेध सूची (Negative List) के अन्तर्गत चिन्हित निम्नलिखित उद्योगों को छोड़कर सभी एकल विनिर्माणक उद्योग।

निषेध सूची:

1. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।
2. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ. 705(ई), दिनांक 02.09.1999 तथा एस.ओ. 698 (ई), दिनांक 17.06.2003 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियां।
4. पौधरोपण, शोधशालायें तथा 10 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन की परियोजनायें।
5. पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाला सामान।
6. कोक (कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाई ऐशा, सीमेंट एवं स्टील रोलिंग मिल।
7. पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।
8. गोल्ड और गोल्ड डोर को छोड़कर।
9. उच्च कीमत के पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर भण्डारण के दौरान संरक्षण, साफ-सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप। हॉस्पिटल, आयुष एवं वैलनेस: कायाकल्प रिसॉर्ट (Spa & Rejunevation Resort), आर्युदेव, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ, होटल, रिसॉर्ट, मोटेल, केबिल कार एवं रोप-वे, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल: बंजी जम्पिंग, पॉवर बोट्स, कायकिंग, जॉय राइडिंग इन चॉपर्स, सी-प्लेन, स्किल गेम पार्क।

iv. सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सिडकुल की वर्तमान भूमि आवंटन नीति के आधार पर समय-समय पर निर्धारित दरों/मूल्य के अनुसार किया जायेगा।

v. इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रु. 50.00 करोड़ अथवा इससे अधिक पूँजी निवेश की नई परियोजनायें- एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण करने वाली इकाईयाँ सम्मिलित होगी।

vi. पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:-

1. लार्ज प्रोजेक्ट्स- ऐसी लार्ज परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रु. 50 करोड़ से रु. 75 करोड़ तक पूँजी निवेश प्रस्तावित हो।

2. मेगा प्रोजेक्ट्स- ऐसी मेगा परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रु. 75 करोड़ से अधिक एवं रु. 200 करोड़ तक पूँजी निवेश प्रस्तावित हो।

3. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- ऐसी अल्ट्रा मेगा परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रु. 200 करोड़ से अधिक एवं रु. 400 करोड़ तक पूँजी निवेश प्रस्तावित हो।

4. सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- ऐसी सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रु. 400 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश प्रस्तावित हो।

vii. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रवृत्त रहेगी और नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।

स्पष्टीकरण: ऐसे उद्योग जो वर्तमान में प्रभावी नीति की मूल वैधता अवधि दिनांक 31.03.2020 से पूर्व स्थापनाधीन/विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर चुके थे, को दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से पहले अपना व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक होगा। दिनांक 31.03.2020 के पश्चात बढ़ाई गयी वैधता अवधि अथवा नयी नीति प्रारंभित होने तक जिन परियोजनाओं की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अर्हता के आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से 30 माह के भीतर उत्पादन प्रारम्भ करने पर ही अनुमन्य होगा।

viii. नीति के अन्तर्गत सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजना हेतु भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत् विशेष छूट/रियायत प्रदान की जायेगी:-

1. लार्ज प्रोजेक्ट्स- सिडकुल की प्रचलित दरों पर 15 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।

2. मेगा प्रोजेक्ट्स- सिडकुल की प्रचलित दरों पर 25 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।

3. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स— सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट ।

4. सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स— सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट ।

स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत पात्र गतिविधियों में समिलित होटल/रिसॉर्ट की स्थापना के लिए सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि (Commercial Activities) के लिए आरक्षित भूमि में, भूमि आवंटन पर भूमि की निर्धारित दरों में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

ix. इस नीति के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 5 वर्ष की समान किरतों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा ।

x. एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नयी परियोजना की स्थापना अथवा विद्यमान परियोजना के विस्तारीकरण के लिए दाखिल Common Application Form (CAF) पर राज्य प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के तीन वर्ष के भीतर उत्पादन में न आने वाले उद्योगों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा । यदि किसी उद्यम ने कोई रियायत/वित्तीय सहायता पूर्व में प्राप्त कर ली हो और वह निर्धारित समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ नहीं करता, तो उसे प्राप्त वित्तीय सहायता ब्याज सहित वापस करना होगा ।

xi. इस नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट/रियायतें निम्नवत होंगी:-

1. ब्याज उपादान : नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से आगामी 5 वर्ष तक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में निम्नवत प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी:-

(क) रु. 50.00 करोड़ से अधिक तथा रु. 75.00 करोड़ तक के लार्ज प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रु. 25 लाख प्रतिवर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता ।

(ख) रु. 75.00 करोड़ से अधिक तथा रु. 200.00 करोड़ तक के मेगा प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रु. 35.00 लाख प्रति वर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता ।

(ग) रु. 200.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रु. 50.00 लाख प्रति वर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता ।

(घ) रु. 400.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रु. 75.00 लाख प्रति वर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता ।

2. एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति: स्वनिर्भित माल/वस्तु के बीटूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी:-

(क) लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू. सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत ।

(ख) मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्पष्टीकरण:

- माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोप में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।
- एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमन्य होगा। विनिर्माणक उद्यम का अर्थ है एक औद्योगिक उपक्रम या कोई अन्य प्रतिष्ठान, जो भी नाम से जाना जाता है, किसी भी तरह से माल के निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है, जो उद्योगों (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951) (1951 का 55) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से सम्बन्धित है और जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्माणक उद्यम में रूप में परिभाषित किया गया हो।
- विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता: पात्र उद्योगों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रु. 1.00 प्रति यूनिट की दर से नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी:—
 - लार्ज प्रोजेक्ट्स— रु. 50 लाख प्रतिवर्ष।
 - मेगा प्रोजेक्ट्स— रु. 75 लाख प्रतिवर्ष।
 - अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स— रु. 1 करोड़ प्रतिवर्ष।
 - सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स— रु. 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष।

स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिह्नित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप-वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को विद्युत बिल में देय प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- इलेक्ट्रिक्सिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति: उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय/भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी की पात्र उद्योगों को शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।
स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिह्नित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप-वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति: उद्यमियों को भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टॉम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

6. भूमि क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निष्पादन हेतु देय/भुगतान किये गये पंजीकरण शुल्क पर प्रति रु. 1000 पर रु. 999 की दर से प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।
7. ई०टी०पी० पर उपादान: उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ETP) की रक्षापना हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 50.00 लाख का पूंजीगत उपादान।
8. बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance : Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रु. 500/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे-रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रु. 700/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: १६७५(१)/VII-A-2/2021/17-उद्योग/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख निजी सचिव, मा० मंत्रीगण को मा० मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव—मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, मंत्रिपरिषद, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक/आयुक्त—उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक—उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की—हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आगामी सरकारी गजट में उक्त सरकारी कार्यालय ज्ञाप की 200 प्रतियां प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

H.

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1671 Dated 21/12/2021

Government of Uttarakhand
Industrial Development Section-2
No.: 556/VII-A-2/2021/17-Industry/2013
Dehradun : Dated: 31 December, 2021

Office Memorandum

Whereas, Mega Industrial and Investment Policy-2015 was promulgated vide Industrial Development Department, Govt. of Uttarakhand, office memorandum no. 556/VII-2/2015/17-Industry dated 28-07-2015 in which from time to time several amendments have been made vide office memorandum no. 1033/VII-1/17-Industry/2013 TC, dated 22nd December, 2016, office memorandum no. 358(1)/VII-1/2018/17-Industry/2013 TC, dated 25th May, 2018 and office memorandum no. 236/VII-A-2/2020/17-Industry/2013 dated 11th June, 2020;

And whereas, with a view to ease and simplification of policy actions, the need for a new integrated policy is being felt, incorporating all the amendments made in the said policy;

Now, therefore, keeping in view the aforesaid the Governor, is pleased to promulgate the following new "Mega Industrial and Investment Policy, 2021" to promote industrialization, increase economic growth rate and create employment opportunities in the state:-

- i. This policy may be called 'the Mega Industrial and Investment Policy, 2021'.
- ii. Under this policy, all industrial estates/areas developed by the State Government (Industry Department/SIIDCUL), notified private industrial estates/areas/special industrial areas, Government of India, Ministry of Finance, Revenue Department's notification number 50/2003-CE dated 10th June, 2003 the Proposed Industrial Estate/Area and Expansion of the Existing Industrial Estates under the head of notified khasra numbers of land or such land legally acquired for mega projects, whose land use is in the approved master plan of the regulated area or the building map has been approved by the competent authority of the concerned regulated area/development authority for the permissible activity of commercial or service sector or the land outside the regulated area (except Municipal Corporation / Municipality / Municipality area) which has been declared as industrial/non-agricultural by the competent authority under section, 143 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) read with rule 135 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and land reforms Rules, 1952 (as amended from time to time) shall be covered.

Explanation: The above provisions shall also be applicable for such projects being set up under Mega Industrial and Investment Policy-2015 (as amended-2016, 2018 and 2020), which have received approval from all concerned departments for the establishment of their project before the implementation of this policy, by obtaining the desired approvals/no objections/permissions, effective steps have been taken for the establishment of the enterprise.

iii. Under this policy, the following identified manufacturing and new projects of the service sector to be established in the Government industrial estates/areas and other identified sites and the existing enterprises/projects having substantial expansion will be eligible for the financial incentives provided in the policy:-

(A) All the single manufacturing industries except the following industries identified under Negative List in Annexure-I of the notification no. F.No. 2(2)/2018-SPS dated 23rd April, 2018 of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Government of India.

Negative List:

1. All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
2. Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
3. Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705 (E) dated 02.09.1999 and S.O. 698 (E) dated 17.6.2003.
4. Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.
5. Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
6. Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash, Cement, Steel Rolling Mills.
7. Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board.
8. Except Gold and Gold Dore.

9. Low value addition activities like preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.

(B) **Hospital, Ayush & Wellness:** Spa & Rejuvenation Resort, Ayurveda, Yoga, Panchakarma, Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy & Spa, Hotel, Resort, Motel, Cable Car & Ropeway, Adventure & Leisure Sports: Bungee Jumping, Power Boats, Kayaking, Joy Riding in Choppers, Seaplane, Skill Game Park.

iv. Allotment of land to desirous entrepreneurs in SIIDCUL industrial areas shall be done on the basis of land allotment policy of SIIDCUL under single window system at the rates/values fixed from time to time.

v. Under this industrial policy, new projects with capital investment of Rs. 50 crore or more and units for expansion of existing projects shall be included.

vi. On the basis of capital investment, projects are classified as follows:-

1. **Large Projects**- Such large projects in which capital investment is proposed to be from Rs. 50 crore to Rs. 75 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

2. **Mega Projects**- Such mega projects, in which capital investment is proposed to be more than Rs. 75 crore and up to Rs. 200 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

3. **Ultra Mega Projects**- Such ultra mega projects, in which capital investment is proposed to be more than Rs. 200 crore and up to Rs. 400 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

4. **Super Ultra Mega Projects**- Such super ultra mega projects, in which capital investment is proposed to be more than Rs. 400 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

vii. This policy shall be effective from the date of issue of notification and shall be in force till 31st March, 2025 and the benefit of financial incentives provided in the policy shall be admissible on starting production during the validity period of the policy.

Explanation: Such industries which had started the work of expansion or establishment before the date 31.03.2020, the original validity period of the policy in force at present, shall be required to start their commercial production before 30th September, 2022. Extended validity period after 31.03.2020 or till the new policy is promulgated to the projects for which in-principle approval has been issued shall be permissible only after starting production within 30 months from the date of issue of in-principle approval on merit basis.

viii. Under the policy, the following special discounts/concessions shall be provided in the current prevailing rates of SIIDCUL in allotment of land for projects in SIIDCUL industrial areas:-

1. **Large Projects**- Rebate on land rate of 15% on the prevailing rates of SIIDCUL.
2. **Mega Projects**- Rebate on land rate of 25% land on prevailing rates of SIIDCUL.
3. **Ultra Mega Projects**- Rebate on land rate of 30% land on prevailing rates of SIIDCUL.
4. **Super Ultra Mega Projects**- Rebate on land rate of 30% land on prevailing rates of SIIDCUL.

Explanation: For the establishment of hotels/resorts included in the eligible activities under the policy, the benefit of exemption in fixed rates of land shall not be admissible on land allotment in the land, reserved for commercial activity in SIIDCUL industrial area.

ix. Under this policy, 20 percent of the value of the land allotted by SIDCUL (after rebate) shall be payable on allotment and the remaining 5 years in equal installments along with fixed interest.

x. The benefit of financial incentives provided in the policy is not admissible to the industries which are not in production within three years of receipt of in-principle approval from the State Authorized Committee on the Common Application Form filed for the establishment of a new project or expansion of the existing project under the single window system. If an enterprise has availed any concession/financial assistance earlier and it does not start production within the stipulated time period, then it shall have to return the financial assistance received along with interest.

xi. The financial incentives and exemptions/concessions provided under this policy will be as follows:

1. **Interest Subsidy:** The following reimbursement assistance shall be admissible to eligible industries to be established under the policy in interest payable on term loans taken from banks/financial institutions for the next 5 years from the date of commencement of production:

- (a) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 25 lakh per annum on Large Projects above Rs. 50 crore and up to Rs.75 crore.
- (b) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 35 lakh per annum on Mega Projects above Rs. 75 crore and up to Rs. 200 crore.

- (c) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 50 lakh per annum on Ultra Mega Projects above Rs. 200 crore.
- (d) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 75 lakh per annum on Super Ultra Mega Projects above Rs. 400 crore.

2. **Reimbursement of SGST:** The maximum limit and quantum of reimbursement of total net SGST payable after adjustment of Input Tax Credit on B2C sale of self-made goods/products shall be as follows:-

- (a) Total net SGST after adjustment of input tax credit for the next 5 years from the date of production for large projects. 30 percent of the tax liability, which is sold to the customer (B to C) within the state.
- (b) Total Net SGST after adjustment of Input Tax Credit for 5 years in advance from the date of production for Mega Projects/Ultra Mega Projects/Super Ultra Mega Projects. Reimbursement of 50% of the tax liability, which is sold to the customer (B to C) within the state.

Explanation:

1. Whatever tax liability is created under the Goods and Services Tax Act, the entire amount related to it will be deposited in the treasury and no share will be kept with itself. Considering the total tax liability as per the return filed and after adjustment of ITC, the unit has to pay such SGST paid under Goods and Services Tax as per the provisions of this scheme. Part of the tax will be reimbursed, which is related to the sale directly to the customer (B2C) within the state.

2. The benefit of SGST reimbursement assistance will be admissible to manufacturing industries only.

"Manufacturing enterprise" means an industrial undertaking or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods in any manner which is a part of the Industries (Development and Regulation Act, 1951) (55 of 1951) belongs to any industry specified in the first schedule, which is defined as a manufacturing enterprise in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

3. **Reimbursement assistance in Electricity Bill:** Reimbursement assistance shall be admissible to the eligible enterprises at the rate of Rs. 1.00 per unit in the electricity bill payable for the next 5 years from the date of commencement of production. The maximum annual limit of

electricity reimbursement assistance shall be as follows:-

- (a) Large Projects - Rs. 50 lakhs per annum.
- (b) Mega Projects - Rs. 75 lakhs per annum.
- (c) Ultra Mega Projects - Rs. 1 Crore per annum.
- (d) Super Ultra Mega Projects - Rs. 1.50 Crore per annum.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance payable in electricity bill shall not be admissible to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals etc. Included in the eligible service activities identified under the policy.

4. **Reimbursement of Electricity Duty:** The eligible enterprises shall be reimbursed 100% of the electricity duty due/paid on the electricity bill consumed in the production work.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance shall not be admissible on electric duty paid to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals etc. involved in the eligible service activities identified under the policy.

5. **Reimbursement of stamp duty:** Entrepreneurs shall be given 50 percent reimbursement assistance on stamp duty charges payable in execution of land purchase deed and lease deed.

6. Reimbursement assistance at the rate of Rs. 999 per Rs. 1000 shall be given on the registration fee payable / paid for execution of land purchase deed / lease deed.

7. **Subsidy on ETP:** Capital subsidy of 30 percent subject to a maximum of Rs 50 lakh for setting up an effluent treatment plant.

8. **Payroll Assistance to encourage massive employment generation:** There shall be a minimum specified limit of regular employment of 50 people for large projects, 100 for mega projects, 200 for ultra mega projects and 400 for super ultra mega projects for allowing payroll assistance. Enterprises where regular employees are employed in excess of the specified limit, shall be given pay-roll assistance as gratuity at the rate of Rs.500/- per employee per month for the next 5 years on the employees employed in addition to the specified limit. For women employees, this rate shall be Rs 700/- per employee per month.

(Amit Singh Negi)
Secretary

No.: 1676(1)/VII-A-2/2021/17-Industry/2013, dated

Copy sent to the following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary, Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand.
2. Principal Private Secretary, Hon'ble Industrial Development Minister, Govt. of Uttarakhand.
3. All Principal Private Secretary, Hon'ble Ministers for the kind perusal of Hon'ble Ministers.
4. Principal Private Secretary-Chief Secretary for the kind perusal of Chief Secretary.
5. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Govt. of Uttarakhand.
6. Secretary, Council of Ministers, Govt. of Uttarakhand.
7. Commissioner, Garhwal and Kumaon Division.
8. All Head of the Department/ Head of the Office, Uttarakhand.
9. All DMs, Uttarakhand.
10. Director General/Commissioner Industries, Directorate of Industry, Dehradun.
11. Director Industries, Directorate of Industry, Dehradun.
12. Managing Director, SIIDCUL, Dehradun.
13. To the Additional Director, Government Press, Roorkee-Haridwar with the intention to publish 200 copies of the said Government Office Memorandum in the upcoming Government Gazette.
14. Guard File.

by order,

Umesh Narain Pandey
Additional Secretary